साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 15-21 जनवरी 2024 वर्ष-9, अंक-40

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बड़ी सौगातः केंद्र सरकार जल्द करेगी ऐलान, किसान सम्मान निधि दोगुनी करने की तैयारी

» देश के कुल किसानों में 60 फीसदी महिलाएं

» सरकार पर 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा

महिला किसानों को हर साल मिलेंगे 12 हजार!

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में इस साल लोक सभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले महिला किसानों को बड़ी खबर मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि डबल करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो महिला किसानों को हर साल 12 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे। फिलहाल सम्मान निधि के रूप में देशभर के किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही सम्मान निधि दोगुनी करने का ऐलान कर सकती है। इससे आम चुनाव में महिला वोटरों का बड़ा समर्थन सरकार को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसका ऐलान होने वाला है। इस फैसले से सरकार पर करीब 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

11 करोड़ किसान ले रहे लाभ - पीएम मोदी ने 2019 के आम चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि देने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक, इस योजना से फिलहाल देश के 11 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है। अब तक इस योजना के जरिए नवंबर तक 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं।

महिलाओं की बढ़ेगी आर्थिक ताकत - किसान सम्मान निधि में इजाफा करने से महिलाओं को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक ताकत में भी इजाफा होगा। किसी सरकारी योजना में कैश सपोर्ट को दोगुना कर महिलाओं को देने का कोई उदाहरण पहले नहीं दिखाई देता। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और मजबूत हो जाएगी।

13 फीसदी महिलाएं ही जमीन की मालिक

देश में इस समय 26 करोड़ किसान हैं। अपने परिवारों की वजह से वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 142 करोड़ की आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 60 फीसदी है। मगर, सिर्फ 13 फीसदी ही जमीन की मालिक हैं। यही वजह है कि सम्मान निधि दोगुना करने के बावजूद सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

फरवरी-मार्च में 16वीं किस्त

केंद्र अभी तक 15 किस्त जारी कर चुकी है। 15 किस्तों में सरकार ने 2.75 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है। बीते 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने 15वीं किस्त के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी की थी। तब 8.5 करोड़ किसानों ने 15वीं किस्त का लाभ उठाया था। अब किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे है। लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव की अचार सहिंता से पहले सरकार फरवरी से मार्च महीने के बीच 16वीं किस्त जारी कर देगी।

मध्यप्रदेश के कसानों को अब हर साल मिलेंगे 18 हजार रुपए

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत चार नहीं छह हजार रुपए सालाना मिल रहे हैं। इस तरह केंद्र ने राशि बढ़ा दी तो किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की योजना से किसानों को 18 हजार सालाना मिलने लगेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को छह हजार का भुगतान करने की मंजूरी दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-2024 से एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर एवं एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किश्तों में कुल छह हजार रुपए का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है।

अमूल-पंचमहल संघ पदाधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक

दुग्ध उत्पाद की सही कीमत के लिए काम करेंगे मप्र-गुजरात

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को दुग्ध उत्पादों की सही कीमत दिलाने के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात के दुग्ध संघ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए दोनों दुग्ध महासंघों की संयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अहमदाबाद में अमूल और पंचमहल दुग्ध संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तय की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने और इस कार्य में लगे किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें सहकारिता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, विपणन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, मानव संसाधन, डेयरी किसानों पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश एवं गुजरात के सहकारी दुग्ध महासंघों और दुग्ध संघों की संयुक्त सहभागिता का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

यह रहे मौजूद

बैठक में प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल, गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) के प्रबंध संचालक जयेन मेहता, पंचमहल दुग्ध संघ के अध्यक्ष जेठाभाई भारवाड तथा प्रबंध संचालक मितेश मेहता, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग गुलशन बामरा, राज्य दुग्ध महासंघ (सांची) के प्रबंध संचालक डा. सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री कंषाना ने क्षतिग्रस्त फसलों का लिया जायजा
मुरैना जिले के 12 गांव ओले से अत्यधिक हुए प्रभावित

ओलावृष्टि से सरसों को नुकसान, रामपुर के गांवों में ओलों की चादर बिछी

मुरैना में ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद

अवधेश डंडोतिया। मुरैना।

कड़ाके की ठंड के बीच बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को सहमा दिया। सबलगढ़ और रामपुर क्षेत्र के कई गांवों में आंधी के साथ ओले गिरे। ओलों की मार से सरसों, गेहूं, चना की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सरसों के खेतों में लहलहा रहे पौधे जगह-जगह से टूटकर धराशायी हो गए। सबलगढ़, रामपुर क्षेत्र में तेज आंधी चली, इसके बाद ओलावृष्टि शुरू हुई। पांच से सात मिनट तक चने से लेकर अंगूर के आकार के ओले तेज रफ्तार में गिरे। सबलगढ़ व रामपुर क्षेत्र के सलमपुर, जलालगढ़, जारेला, धरसोला, सिमरौदा अहीर, सिमरौदा किरार, सेमई और नौरावली गांव के अलावा कैलारस के भी कुछ गांवों में ओलावृष्टि व तेज बारिश हुई है। रात में हुई ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी। चना व गेहूं के पौधे खेतों में पसर गए, जबकि सरसों की हालत सबसे बुरी थी। सरसों के पौधों में एक भी फूल नजर नहीं आ रहा था। ओलों की मार से सरसों के फूल सहित पौधे के तने जगह-जगह से टूटकर खेतों में धराशायी हो गए। खेतों के बीच और आसपास ओलों की चादर सी बिछी मिली। किसानों के अनुसार सरसों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है।

सरकार करेगी किसानों की भरपाई

इधर, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने मुरैना जिले के सबलगढ़ के 6 गांवों का भ्रमण कर क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ओला पीड़ित किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। 50 प्रतिशत नुकसान पर किसानों को आरबीसी-6 (4) में शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने ग्राम पंचायत सिमरोदा किरार के गयेराम की ओला प्रभावित शत-प्रतिशत क्षतिग्रस्त सरसों की फसल का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि संकट के समय में प्रदेश सरकार उनके साथ है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने अधिकारियों को ओले से प्रभावित सरसों की फसल का मौका-मुआयना कर राहत राशि प्रदान करने की समस्त आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुरैना जिले के 12 गांव ओले से अत्यधिक प्रभावित हुए थे।

पुलिस ने भी समय पर नहीं की मदद, किसानों में पनप रहा आक्रोश

ग्वालियर में ठग व्यापारी अन्नदाताओं को लगा गए 25 लाख का चूना

ग्वालियर। जागत गांव हमार

ग्वालियर जिले में किसानों से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह ठगी फर्जी व्यापारियों द्वारा की गई है। व्यापारी बनकर आए कुछ ठगों ने गांव-गांव घूमकर किसानों की धान खरीदी। लेकिन जब भुगतान का समय आया तो वे रातों-रात वहां से रफूचक्कर हो गए। अब तक दर्जनों पीड़ित किसान पुलिस के पास पहुंचे हैं और लगभग 25 लाख की ठगी का पता चल सका है। यह मामला भितरवार इलाके में उजागर हुआ है। इस इलाके में धान की फसल खूब होती है और व्यापारी यहां खरीद करने आते हैं। इस बार भी किसानों के पास कुछ व्यापारी गाड़ियों से पहुंचे। लेकिन किसान समझ नहीं पाए कि ये व्यापारियों के भेष में ठग हैं। ठगी का शिकार एक किसान अनिल बाथम का कहना है कि धान खरीदी के लिए गाड़ियों से कुछ व्यापारी उनके क्षेत्र में आए। उन्होंने अपने को झांसी और दतिया का व्यापारी बताया। व्यापारियों ने राजन के मंदिर पर अपना फड़ लगाया। वहीं, धान की तुलाई करके ट्रकों से लादकर माल भेज दिया और 15 दिन बाद भुगतान के लिए आने की बात कहकर चले गए। फिर लौटकर नहीं आए। एक अन्य किसान अरविंद सिंह राणा ने भी बताया कि कुछ व्यापारियों ने उनकी फसल खरीदी, जिसमें 25 किसानों ने अपनी फसल व्यापारियों को बेची थी। व्यापारियों ने फसल के पैसे अदा नहीं किए और भाग गए।

24 किसानों से 25 लाख की ठगी- इस मामले में अब तक सिर्फ किठौंदा गांव के ही 24 पीड़ित किसान सामने आ चुके हैं, जिनसे उन फर्जी व्यापारियों ने धान खरीदी और भाग गए। इनको लगभग 25 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला उजागर हो चुका है।

पुलिस ने नहीं की समय पर मदद

पीड़ित किसानों की शिकायत है कि पुलिस ने समय पर हम लोगों की मदद नहीं की। किसानों ने बताया कि ग्रामीणों ने उसी समय थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि व्यापारियों ने उनकी धान खरीदी और उनकी फसल का पूरा पैसा लेकर भाग गए हैं। सभी किसानों ने आवेदन देकर भितरवार थाने में शिकायत भी की थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने पहले उनकी कुछ गाड़ियां जब्त कर ली थी और थाने में रखवा दी गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी गाड़ियां छोड़ दी गई और उन्हें पुलिस के द्वारा भी कोई न्याय नहीं मिला।

अब पुलिस ने किया केस दर्ज

इसके बाद अब पीड़ित किसान एक बार फिर इकट्ठे होकर भितरवार थाना पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का आपराधिक केस दर्ज किया है। एडिशनल एसपी देहात निरंजन शर्मा ने बताया कि इस मामले में लगभग 25 लाख की धान खरीदी कुछ समय पूर्व की गई थी। लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया था। किसानों के आवेदन पर पुलिस ने भितरवार थाने में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सभी आरोपी झांसी और दतिया जिले के हैं।

पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा

अब तूर के अलावा अन्य दालों की बिक्री भी सरकारी पोर्टल पर होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों की आय और उपज बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। डिजिटल तरीके से किसानों को सीधे देशभर के तमाम बाजारों से जोड़ा रहा है ताकि उनकी फसल का सही दाम उन्हें मिल सके और भंडारण में होने वाले खर्च से बचाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा है कि तूर दाल की बिक्री के लिए लॉन्च हुए ई-पोर्टल पर किसान अन्य दालों को भी बेच सकेंगे। पोर्टल पर बिक्री के लिए एमएसपी रेट पर सरकार दाल खरीद करेगी।

पीएम ने योजनाओं के लाभार्थियों से बात की- विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और किसानों को दिए जा रहे लाभों पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि हमारे देश में किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था। किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्दगिर्द तक सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पात्र किसानों के खाते में कम से कम 30 हजार पहुंचे

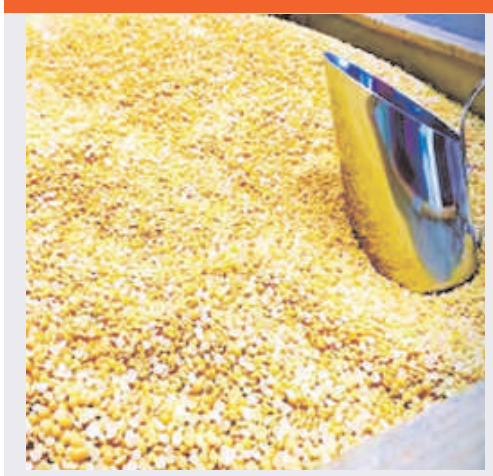

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है। छोटे किसानों के ऐसे संगठन आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। भंडारण की सुविधा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं।

एमएसपी पर खरीद की गारंटी के साथ बाजार में भी बेहतर मिलेगा

पीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले सरकार ने दाल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। किसानों को दाल बिक्री के लिए सरकार ने पोर्टल ई-समृद्धि लॉन्च किया है। अब दाल उत्पादन करने वाले दाल किसान इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दालें बेच पाएंगे। इसमें दाल किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि अभी ये सुविधा तूर या अरहर दाल के लिए दी गई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि दाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेजते हैं, वो देश के ही किसानों को मिल सके।

पोर्टल पर दाल बिक्री होते ही किसानों के खाते में पहुंचेगा पैसा

सहकारी समितयां नेफेड और एनसीसीएफ ने दाल किसानों के लिए ई-पोर्टल ई-समृद्धि को विकसित किया है। पोर्टल की मदद से किसान सीधे अपनी दाल को ऑनलाइन बेच कर सीधे उसका भुगतान नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए तुरंत अपने अकाउंट में पा सकेंगे, जबकि, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों से सहकारी समितियां भी संपर्क कर उनसे दाल खरीदेंगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों या व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इससे पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जबकि, दाल की सीधी खरीद से बफर स्टॉक बढ़ेगा और इससे आयात की निर्भरता घटेगी।

बड़वानी में सीसीआई के कपास खरीदी केंद्र का शुभारंभ

बड़वानी। कृषि उपज मंडी समिति बड़वानी के प्रांगण में शुभ मुहूर्त में राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के कपास खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। सांसद सोलंकी ने बताया कि बड़वानी क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें अपना कपास बेचने अंजड़ या फिर सेंधवा जाना पड़ता था अथवा स्थानीय स्तर पर औने- पौने दाम पर कपास बेचना पड़ता था। लेकिन अब जिला मुख्यालय पर सीसीआई का खरीदी केंद्र प्रारंभ हो गया है। इससे किसानों को सुविधा हो जाएगी। इस केंद्र को प्रारंभ करने के लिए क्षेत्रीय लोक सभा सांसद श्री गजेंद्र पटेल और मैंने सीसीआई के उच्च स्तरीय अधिकारियों से पत्राचार कर आग्रह किया था कि यहां पर सीसीआई का कपास खरीदी केंद्र आरंभ किया जाए। जिसे स्वीकार कर यह केंद्र शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले दिन कपास की आवक 500 क्विंरही। समर्थन मूल्य भाव 6920 रुपए क्विंटल के भाव से खरीदी की गई है। सप्ताह में दो दिन गुरुवार, शुक्रवार को सबुह 11.30 से दोपहर 2 बजे तक बड़वानी मंडी में समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी की जाएगी।

अर्जुन मुंडा बोले- इस क्षेत्र में हैं विकास की अपार संभावनाएं

350 मिलियन टन हुआ बागवानी का उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

बागवानी के क्षेत्र में भारत ने काफी तरक्की की है। साथ ही यह काफी तेजी से यह क्षेत्र वृद्धि दर्ज कर रहा है। वर्ष 2022-23 में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन 350 मिलियन टन हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र में अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस उद्देश्य के साथ केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेंगलुरू में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर) का दौरा किया। यहां किसानों, विद्यार्थियों व वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने किसान सुविधा काउंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एमओयू भी किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आईआईएचआर 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देशभर के किसानों के लाभ के लिए उष्णकटिबंधीय फलों, सब्जियों व फूलों की फसलों सहित बागवानी फसलों की 300 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। संस्थान ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी का योगदान 33 प्रतिशत है, जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी काफी संभावनाएं है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम न केवल घरेलू बाजार में बल्कि दुनिया के बाजारों में और बेहतर ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।

बागवानी क्षेत्र में हुई है वृद्धि

बागवानी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण घटक माना जा रहा है। यह क्षेत्र नए तरीके से अपनी आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत में बागवानी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान 350 मिलियन टन हो गया है। उन्होंने बागवानी उत्पादों के भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन के महत्व को समझाया व किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन का लक्ष्य रखने का अनुरोध किया, ताकि उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक किसानों को अपनी प्रयोगशालाओं में लाने और नवीनतम अनुसंधान तकनीकों को उनके साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे किसानों को उत्पादकता, पैदावार व आय को टिकाऊ तरीके से बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सभी खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भरता होना चाहिए

अर्जुन मुंडा ने कहा कि दलहन उत्पादन बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम करने व प्रौद्योगिकी के समर्थन की आवश्यकता है। सभी खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भरता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के माध्यम से आदिवासी समुदाय को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का काम किया जा रहा है।

जबलपुर। जिले में धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल का असर दिखने लगा है। धान बेचने के लिए किसानों द्वारा कराए गए फर्जी पंजीयन की जांच अब अंतिम दौर पर है। अब जिला प्रशासन धान बेचने के दौरान उपार्जन केंद्र आने वाले पंजीकृत किसानों की आईडी और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद ही खरीदी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। दरअसल जिले में लगभग 55 हजार में से 54 हजार किसानों ने सिर्फ धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। प्रशासन की गोपनीय टीम को इसमें से 40 फीसदी पंजीयन फर्जी मिले। इतना ही नहीं इस बार जिले से 12 हजार से ज्यादा सिकमीनामे हुए, जिनकी भी अब जांच शुरू होने जा रही है।

» इस बार जिले से 12 हजार से ज्यादा सिकमीनामे हुए

» परेशान किसानों से कहा- गीले धान से खत्म करें नमी

उपार्जन केंद्र में धान तुलाई के दौरान हुए फर्जी पंजीयन की अब होगी जांच

जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्र में धान की गुणवत्ता जांचने का काम जबलपुर की बजाए भोपाल के सर्वेयर करेंगे। भोपाल से सर्वेयर की टीम शहर आई। इनकी बैठक लेते हुए नवागत कलेक्टर दीपक सक्सेना से इन्हें ब्लाक लिस्ट में दर्ज 36 वेयरहाउस में बाहर और अंदर रखी धान की गुणवत्ता जांचने का जिम्मा दिया है। दो दिन पूर्व शहर और आसपास के जिलों में हुई बारिश की वजह से गोदाम के बाहर रखी धान में पानी भर गया, जिससे उसमें नमी हो गई है। प्रशासनिक के अनुमान बारिश की वजह से अधिकांश वेयरहाउस में बाहर लगभग 18 मैट्रिक टन धान गीली हो गई। इससे उसमें नमी आ गई है। अब किसानों को कहा गया है कि वे इसकी नमी को कम करें, ताकि प्रशासन इसे खरीद सकें। हालांकि वेयरहाउस में बाहर बड़ी मात्रा में खुले में पड़ी धान किस किसान की है, इसकी पहचान को लेकर असंमजस्य बना हुआ है।

किसानों का कहना है कि उन्हें पता है कि हमारी धान कहां और कितनी रखी है। इस वजह से धान की तुलाई में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तुलाई के पहले धान की गुणवत्ता की भी जांच अहम हो गई है। इस वजह से सर्वेयर की भूमिका अब और बढ़ गई है, लेकिन पहले ही सर्वेयर के काम को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है।

नए और पुराने बारदाने का खेल शुरू

जिले में ब्लैक लिस्ट में दर्ज 36 वेयरहाउस में से 12 ऐसे वेयरहाउस हैं, जहां बड़ी मात्रा में धान बिना पंजीयन के वेयरहाउस में अंदर रख ली गई है। इन वेयरहाउस द्वारा पुराने बारदाने का उपयोग किया गया। अब जब प्रशासन इस धान की जांच करेगा तो धान नए बोरे में रखी जाएगी। इस बीच बोरे की अदला-बदली में खेल होगा। वहीं दूसरी ओर बिना पंजीयन धान रखने वाले वेयरहाउस में मिले सरकारी वारदान की जांच अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर प्रशासन ने अभी भी कोई बड़ा कदम नहीं हुआ है। आखिर यह सरकारी बारदाना कहां से आए गए। कटनी के जिस ठेकेदार को बारदाना सप्लाई का काम दिया है, उसकी भी इन वेयरहाउस के साथ सांठगांठ सामने आई है।

21 केंद्रों से होगी 36 गोदाम की धान जांच

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सुबह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सर्वेयर्स की बैठक ली। उन्होंने सभी गोदामों में रखी धान का गुणवत्ता परीक्षण तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जहां शासन से खरीदी केंद्र बनाने की स्वीकृति मिले बगैर किसानों द्वारा अपनी उपज का भंडारण कर लिया गया है। इन अनाधिकृत स्थानों पर रखी किसानों की धान की खरीदी दो या तीन दिन में शुरू की जानी है, इसलिये सर्वेयर्स को इन से गोदामों में रखी धान का परीक्षण प्रारंभ करना होगा।

मापदंडों का कड़ाई से पालन करें

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सर्वेयर्स को हिदायत दी कि धान के परीक्षण में एफ ए क्यू मापदंडों का कड़ाई से पालन करें। गुणवत्ता की जांच के दौरान उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अनाधिकृत स्थानों पर रखी धान में से केवल वास्तविक किसानों की धान ही खरीदी जाना है। वहीं बिचौलिये या व्यापारी की गतिविधियों का भी ध्यान रखा जाएगा।

किसानों से मिले कलेक्टर

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रविवार को कई गोदामों का निरीक्षण किया। इनमें अधिकांश ब्लैक लिस्ट में आने वाले वेयरहाउस रहे। कलेक्टर ने किसानों से चर्चा की तथा उन्हें वास्तविक किसानों की एफ ए क्यू गुणवत्ता वाली पूरी-पूरी धान खरीदने का भरोसा दिया। वे मझौली तहसील पहुंचे और ग्राम पिपरिया स्थित श्री अन्नपूर्णा वेयर हाउस और ग्राम चोपरा स्थित ओम साईं राम एग्रो वेयर हाउस स्थित उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी गई धान का निरीक्षण किया।

उपज खरीदी केंद्रों पर लाएं

कलेक्टर ने किसानों से चर्चा में असुविधा से बचने के लिए स्लॉट बुक करके ही अपनी उपज खरीदी केंद्रों पर लाने का आग्रह किया। कलेक्टर ने मझौली तहसील के अंतर्गत योगमाया वेयर हाउस बटरंगी, ओम साईं राम वेयर हाउस मुड़कुरु, सिद्धार्थ वेयर हाउस घाना कला जैसे उन गोदाम परिसरों में रखी धान का जायजा भी लिया।

अन्नदाता की उपज को खरीदने की व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा प्रशासन

पाटन में खुले में पड़ा किसानों का हजारों क्विंटल धान भीगा

जबलपुर। जागत गांव हमार

धान खरीदी में हो रही भारी अनियमितता के बाद किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिले के पाटन और मंझौली के किसानों ने शुक्रवार को वेयरहाउस के बाहर पड़ी धान के बारिश में गीले होने और अब तक इसे वेयरहाउस में न शिफ्ट किए जाने का जमकर विरोध हुआ।

सैकड़ों किसानों के भोजन की व्यवस्था की- पाटन तहसील मुख्यालय में किसान संघ के पदाधिकारी धरना स्थल पर आए और सैकड़ों किसानों के भोजन की व्यवस्था की। धरना स्थल पर किसानों द्वारा गकड़ भर्ता बनाया गया और किसानों के साथ साथ सुरक्षा में लगे पुलिस महकमे व प्रशासन को भी भोजन कराया। इस दौरान किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष ओमनारायण पचौरी, जिलाध्यक्ष मोहन तिवारी, उपाध्यक्ष दामोदर पटेल, विवेक बेहुरे, राजकुमार वाजपेई, सुनील पटेल आदि है।

प्रशासन इसमें नाकाम रहा

भारतीय किसान संघ ने बताया कि जिला प्रशासन को धान खरीदी के लिए अल्टीमेटम दिया था, बावजूद इसके प्रशासन इसमें नाकाम रहा। जिसके कारण जिले के किसानों ने पाटन व मंझोली के किसान तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मोहन तिवारी ने बताया कि धान खरीदी की व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय किसान संघ ने 15 सूत्रीय मांगों के सुझाव जिला प्रशासन को दिए थे। जिन पर कार्रवाई करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा है।

मौसम खराब है और किसानों की धान खुले में पड़ी

धान खरीदी की गति बहुत धीमी चल रही है और धान का परिवहन व भंडारण भी नहीं हो रहा है। जिसके कारण जिले का धान उत्पादक किसान परेशान है। पाटन तहसील अध्यक्ष रामकृष्ण सोनी ने कहा है कि यदि किसानों की धान खरीदी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जबलपुर के किसान दो दिन बाद अपनी धान लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अपनों मांगों का ज्ञापन एस डी एम पाटन मानवेंद्र सिंह को किसानों से सौंपा।

रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा

डा. आनंद प्रकाश शुक्ला

भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कृषि दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हालांकि 2016 से 2019 तक कुल उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत से घटकर 13.4 प्रतिशत हुई है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र से होने वाला पूर्ण उत्सर्जन 3.2 प्रतिशत बढ़ गया, जो 421 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष तक पहुंच गया। कृषि के कारण कुल उत्सर्जन 4.5 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 2,647 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो 2016 में 2,531 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड था।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सौंपे गए तीसरे नेशनल काम्युनिकेशन एंड इनिशियल एडप्टेशन कॉम्युनिकेशन में इसकी सूचना दी गई है।

कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का स्रोत पशुधन की वजह से होने वाले मीथेन से उत्पन्न होता है, जो मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों में पाचन प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के स्रोत चावल की खेती और कृषि मिट्टी से उत्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड हैं।

कृषि अवशेषों को खेत में जलाने से अतिरिक्त उत्सर्जन: सामूहिक रूप से, ये स्रोत कुल कृषि उत्सर्जन में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। कृषि अवशेषों को खेत में जलाने से भी अतिरिक्त उत्सर्जन होता है। दिलचस्प बात यह है कि खेतों में कृषि अवशेष जलाने को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन में वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पशुधन से मीथेन उत्सर्जन में 0.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, जो कि पशु आबादी में वृद्धि के कारण है, जिसमें क्रॉस-ब्रीड मवेशियों की संख्या में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि भी शामिल है।

चावल से मीथेन उत्सर्जन 3 प्रतिशत बढ़ा: खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से चावल से मीथेन उत्सर्जन 3 प्रतिशत बढ़ गया। 2016 में चावल का क्षेत्रफल 43.1 मिलियन हेक्टेयर था जो 2019 में 43.6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। हालांकि, इसी समय अवधि के दौरान, चावल की खेती से पानी बचाने और मीथेन उत्सर्जन को कम करने वाले कई जल वातन व्यवस्था की हिस्सेदारी 2016 में 12.4 प्रतिशत से बढ़ कर अब 21.9 प्रतिशत हो गई है, जो 9.5 प्रतिशत अंकों की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है।

सिंथेटिक उर्वरक की वृद्धि से बढ़ रहा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन: मिट्टी से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 13.6 प्रतिशत की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, जिसका श्रेय सिंथेटिक उर्वरक-आधारित नाइट्रोजन की खपत में वृद्धि को दिया गया। जबकि खाद प्रबंधन ने क्षेत्र के उत्सर्जन में 1 प्रतिशत की वृद्धि का योगदान दिया, फसल अवशेष जलाना कृषि के भीतर एकमात्र उप-क्षेत्र था जिसने 5.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

जबकि भारत की स्वैच्छिक घोषणा में कृषि में विशिष्ट शमन गतिविधियों और उत्सर्जन में कटौती को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक जीवित उत्सर्जन पर विचार करते हुए, रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में कृषि उप-क्षेत्रों में उठाए गए अनुकूली उपायों के बारे में बताया गया है, लेकिन कृषि उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने के बावजूद, विशेष रूप से पशुधन क्षेत्र से जुड़े किसी भी अनुकूलन उपायों की अनदेखी की गई है।

रिपोर्ट में मिट्टी से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ रहा है, यह तो बताया गया है, लेकिन कौन सी फसलें और मिट्टी कितना उत्सर्जन कर रही हैं, इसका विवरण गायब है।

2050 तक 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी समस्या: एक अनुमान के मुताबिक, तेजी से नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। वैसे तो भारत में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती और कांट्रेक्ट फार्मिंग करने वाले किसान और कंपनियां तो आवश्यकतानुसार इनका इस्तेमाल करती ही हैं।

कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक, लगातार नाइट्रोजन उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण साल 2050 तक इसकी खपत 50 फीसदी तक बढ़ सकती है। इससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन में भारी बढ़त होगी और पेरिस समझौते के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है।

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा: धरती पर इंसानों के साथ-साथ कई जीव-जानवर रहते हैं। बेशक इन नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए किया जाता है, लेकिन ये हवा, पानी, भूजल, मिट्टी और वातावरण में फैलकर दूसरे जीव-जंतुओं के लिए खतरा बन रहे हैं। इस मामले में वैज्ञानिक भी यही सुझाव देते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक और दूसरे रसायनों का इस्तेमाल रोककर टिकाऊ खेती पर जोर देना चाहिए। हमें खेती के लिए उन पद्धतियों को अपनाना होगा, जो खेती का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हों।

आलू की उन्नत खेती: जानिए कैसे पाएं ज्यादा पैदावार

» डॉ. दिनेश कुमार कुलदीप
» डा. एन आर रंगारे
» डा. मनमोहन सिंह भूरिया
» डा. डॉ सौरव गुप्ता

विषय विशेषज्ञ, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

कृषि विज्ञान केंद्र,खंडवा(म.प्र.)

आलू देश की महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसलों में से एक है इसकी औसत पैदावार 200-250 कुं. प्रति हेक्टयर है, इससे बनने वाली खाद्य सामग्री इसे और अधिक रोचक बना देते हैं। जैसे- फिगंर चिप्स, (फेंच फ्राईस) आलू चिप्स, मुरब्बा आदि। यदि उत्तम किस्मों और नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए तो इसकी पैदावार को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। आलू को अच्छी जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ से भरपूर बलूई दोमट मिट्टी में लगाएं। पानी ठहरने वाली क्षारीय मिट्टी में आलू की फसल नहीं उगानी चाहिये। पी.एच.मान-5.2-6.8 आलू की अच्छी बढ़वार के लिए हल्की जलवायु की आवश्यकता होती है।

मिट्टी व जलवायु: आलू को अच्छी जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ से भरपूर बलूई दोमट मिट्टी में लगाएं। पानी ठहरने वाली क्षारीय मिट्टी में आलू की फसल नहीं उगानी चाहिये। पी.एच.मान-5.2-6.8 आलू की अच्छी बढ़वार के लिए हल्की जलवायु की आवश्यकता होती है। कंद बढ़ने व फूलने के समय क्रमश: 18-20 सेटीग्रेट एवं 20-24 सेटीग्रेट तापमान की स्थिति को अच्छा माना जाता है। अधिक तापमान कंद बनने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं।

बीजोपचार: आलू की बीज सरकारी संस्थानों से खरीदें। आलू का बीज तीन चार साल बाद अवश्य बदल दें वरना बीज में विषाणु रोग बढ़ने की संभावना रहती है। अच्छे अंकुरित वाले 30-40 ग्रा. भार का आलू के बीज को बुआई से 10 दिन पूर्व ठंडे गोदाम से निकालें। पहले बीज को 24 घण्टे के लिए प्रोकुलिंग चेम्बर में रखे इसके पश्चात बीज को छाया वाली जगह में रखे। इसी दौरान सड़े हुए व बिना अंकुरित हुये आलू निकाल दें।

महत्वपूर्ण किस्म एवं संकर किस्म: अगेति किस्म: कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति।

मध्य किस्म: कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी लालिमा, कुफरी शीतमान, कुफरी स्वर्णा, कुफरी नवीन, कुफरी सतलज, कुफरी चिप्सोनों-1 कुफारी चिप्सोना-2

पिछेती किस्त: कुफरी नीलमणी, कुफरी जीवन, कुफरी सिन्दूरी, कुफरी किसान।

बुआई का समय: आलू की बुआई का उचित समय अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा है। यह समय इसलिये उपयुक्त है क्योकिं जिन स्थानों पर पाला दिसम्बर के आखिर माह में या जनवरी के प्रथम माह में पड़ता है। अत: पाला पड़ने तक आलू को बड़ने के लिए पूरा समय मिल जाता है।

बुआई विधि: शीत गृहों से कंदिय बीज बुआई से 10-15 दिन पहले प्राप्त कर लेना चाहिये। इन कंदिय बीज को बाल्टी या प्लास्टिक की रैक में फैला देना चाहिए। कंद के आधार पर बुआई हेतु बीज से बीज की दूरी निम्नानुसार होती है।

कंदों को खेत में तैयार क्यारियों की कतार में लगाया जाता है, जो खेत की ढलान के अनुरुप छोटी लंबी होती है। अर्थात कम ढलान कम लंबाई एवं अधिक ढलान में क्यारियों की ज्यादा लंबाई रखनी चाहिये। बुंआई के लिए कतारों को संकरी कुदाली से खोदकर, बीज कंदो में अनुशंसित दूरी पर लगाने के बाद ढंक दें बुआई के तुरंत बाद सिंचाई की जाती है। ताकि जड़ अच्छे से फैले तथा अच्छी उपज प्राप्त हो।

खाद उर्वरक: उचित मात्रा में उर्वरक के साथ आलू का उत्पादन वृहत रुप से बढ़ाई जा सकती है। भूमि तैयार करते समय कम्पोष्ट या एफ.वाय.एम. (गोबर की खाद) का अवश्यक रुप से उपयोग करने से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आवश्य है। जुताई के समय अच्छी तरह से सड़ी गोबर की खाद 200-250 क्विंटल प्रति हेक्टयर मिलाई जानी चाहिए। इसके साथ 100-150 किलो नत्रजन 80-100 किलो स्फूर एवं 80-100 किलो पोटाश प्रति हेक्टयर आलू की बेहतर उपज के लिए आवश्यक है। बुआई के समय नाइट्रोजन की 2/3 से 3/4 मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा डाली जानी चाहिए। कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे बोरॉन, जिंक, मॉल्ब्डिेनम , तांबा का भी प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए।

सिंचाई: बुआई के समय भूमि में उचित नमी होना आवश्यक है। ताकि जड़े अच्छे से विकसित हो सकें। भूमि में नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। सामान्यत: सिंचाई 7-10 दिन के अंतराल पर फ्लड विधि के द्वारा करनी चाहिए इस प्रकार आलू की फसल में 6-8 सिंचाई की आवश्यकता होती है। आलू की खुदाई करने के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। जिससे आलू के कंदो का छिलका कठोर हो जाए।

मिट्टी चढ़ाना: पौधे में 30-35 दिन पश्चात पहली गुड़ाई करनी चाहिए इस समय तक पौधे 20-30 से.मी. ऊँचे हो जाते है। इस समय नाइट्रोजन (नत्रजन) की शेष मात्रा दी जानी चाहिए। प्राय: मिट्टी चढ़ाने के दो सप्ताह बाद दूसरी बार भी मिट्टी चढ़ाना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने में कंदो की बढ़वार अच्छी होती है। साथ ही वे हरा होने से बच जाते है।

खरपतवार नियंत्रण: खरपतवार नियंत्रण हेतु 1.00 कि. नाइट्रोकेन अथवा एलाक्लोर की 2 कि. मात्रा प्रति हेक्टयर इस्तेमाल की जानी चाहिए जिससे निंदाई के समय मानव श्रम पर होने वाली लागत से बचा जा सकता है।

खुदाई उपज एवं भण्डारण: जब आलू की पत्तियां सूखने लगे तो आलू की खुदाई करने से 10-15 दिन पूर्व पौधों की शखाओं को जमीन की सतह से काट देना चाहिए। ताकि कंद के छिलके मोटे हो सकें, खुदाई के बाद कंदो को ढ़ेर बनाकर 15 दिनों के लिए रख देना चाहिए, शीत भण्डारण के लिए तापमान 2-4 सेटीग्रेट होना चाहिए मैदानी क्षेत्रों में अगेती एवं मध्य किस्में से 200-500 क्विंटल/हे. और पिछेती किस्मों से 300-400 क्विंटल/ हे. उपज प्राप्त हो जाती है।

विटामिंस के अच्छे स्रोत मोटे अनाज, गुणों की खान

मोटे अनाज में कई तरह के महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। यह शिशु तथा गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार है। मोटे अनाज पोषक गुणों से परिपूर्ण पाया गया है। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले वर्ग मडुआ उपभोग करना चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अधिक पसंद करता है क्योंकि यह शक्ति का उत्तम साधन है। प्राय: इसके दाने को पीसकर आटा बनाया जाता है, जिससे केक खीर तथा पकवान तैयार की जाती है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसके लड्डू बनाकर कलेवा के काम में लाया जाता है। मधुमेह के रोगी, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताएं, बढ़ते हुए शिशु तथा गर्भवती स्त्रियों के लिए मडुआ एक आदर्श आहार है क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहा जाता है कि मडुआ का प्रोटीन दूध के प्रोटीन के समान ही गुणकारी होता है। इसके पोषक गुणों के कारण इससे मडुआ मार्ट बेंगलुरू की एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इसे विभिन्न आकार के डिब्बों में भरकर बाजार में बेचा जाता है। मोटे अनाज अत्यंत पोषक भोजन है तथा इसकी तुलना बॉर्नविटा या माल्टोवा से की जा सकती है। इसका उपभोग दूध, चाय, या पानी में मिलकर किया जा सकता है। देश के उत्तरी भागों में विशेष कर पहाड़ों में या पूर्वी भागों में उदाहरणत: पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा उड़ीसा में इसे चावल की भांति प्रयोग किया जाता है। इसके आटे से चापातियां भी बनाई जाती है। उक्त कथित प्रयोगों के अतिरिक्त मडुआ के उगाए गए दानों को माल्टिंग (शराब या अल्कोहल) के लिए प्रयोग करके बीयर और शराब तैयार की जाती है। इसके बादामी रंग का प्रभाव इन औद्योगिक पदार्थों के रंग पर भी पड़ता है जिसके कारण इनका मूल्य कम मिलता है। कहा जाता है कि मडुआ से तैयार की गई बियर का स्वाद प्राय: उपभोक्ताओं को पसंद नहीं है।

मोटे अनाज में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक मडुआ में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। हड्डियों को कमजोर होने से हुई बीमारियों में इसे खाने की सलाह दी जाती है। यही नहीं बढ़ते बच्चों के लिए यह फायदेमंद है। मडुआ का आटा खाने से त्वचा जवां बनी रहती है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड से स्कीन के टिशू झुकते नहीं है। इसलिए झुरिया नहीं बनती जिसे चेहरा ग्लो करता है। मडुआ के आटे में विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसके आटे में आयरन भी प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। एनीमिया और कम हीमोग्लोबिन से जूझ रहे मरीजों के लिए भी इसे खाना लाभदायक है। इन अनाजों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन बहुत कम है। लगभग सभी मोटे अनाजों को समाज का निर्धन वर्ग भोजन के रूप में प्रयोग करता है।

भिंड-मुरैना में पिछले साल की तुलना में कम में खेती

मुरैना, भिंड और श्योपुर में पिछले साल की तुलना में कम खेती

मुरैना। जागत गांव हमार

चंबल सरसों की खेती के लिए पूरे देश में ख्यात है। यहां के सरसों तेल की मांग विदेश तक है। इसीलिए, बीते दो दशक से चंबल के मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों में सरसों की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन बीते दो बरस से सरसों के भाव में बढ़ोतरी की जगह गिरावट होने से किसानों का मन इसकी खेती से उचट गया है। चंबल के तीनों जिलों में सरसों का रकबा पिछले साल की तुलना में इस साल 55717 हेक्टेयर घट गया है।

किसानों में इसकी खेती के प्रति कम हुए रुझान को इस तरह समझें- चंबल का भिंड जिला पूरे मप्र में सरसों उत्पादन में अव्वल है। यहां पिछले साल सरसों की खेती दो लाख 30 हजार 235 हेक्टेयर में हुई, जो इसके पिछले साल से 8205 हेक्टेयर अधिक था। इस बार एक लाख 80 हजार 200 हेक्टेयर में खेती हुई है, यानी रकबा 50035 हेक्टेयर घट गया है। इसी तरह पिछले साल मुरैना में 1000 हेक्टेयर में सरसों की खेती का दायरा बढ़ा, जिसकी तुलना में इस साल 1282 हेक्टेयर में खेती कम हुई है। श्योपुर में पिछले साल की तुलना में 4400 हेक्टेयर में सरसों की फसल नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि अंचल के सवा तीन लाख से ज्यादा किसान परिवारों की मुख्य आय का स्रोत सरसों की खेती ही है। खेतों में सरसों की फसल कम होने के साथ मुरैना में तेल मिल भी बंद होती जा रही हैं। जिले में 40 बड़ी तेल मिलें हैं, जिनमें से 34 पर ताला लगा है, पांच-छह बड़ी मिल ही चालू हालत में हैं, जो ब्रांडेड कंपनियों को तेल सप्लाई करते हैं।

सरसों का दाम घटने से चंबल में घट गया फसल का रकबा

चंबल में ऐसे लुढ़का सरसों की खेती का ग्राफ

भिंड में पिछले साल दो लाख 30 हजार 235 हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई। इस बार एक लाख 80 हजार 200 हेक्टेयर के करीब रकबा रह गया। यानी 50035 हेक्टेयर कम में खेती। मुरैना में पिछले साल एक लाख 77 हजार 100 हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई। इस बार एक लाख 75 हजार 818 हेक्टेयर में बोवनी हुई। यानी 1282 हेक्टेयर रकबा कम हो गया। श्योपुर में पिछले साल 73 हजार 400 हेक्टेयर में खेती हुई थी। इस साल रकबा 69000 हेक्टेयर पर सिमट गया। यानी 4400 हेक्टेयर कम में खेती।

विदेशी तेलों की आवक से इस तरह प्रभावित हैं किसान

साल 2020-21 में केंद्र सरकार ने विदेश से आ रहे तेलों पर आयात कर दोगुना से ज्यादा कर दिया था और मिश्रित तेल (ब्लेंडेड आयल) के लाइसेंस रद कर दिए थे। इससे बाजार में सरसों तेल की मांग ऐसी बढ़ी कि इसका भाव 200 रुपए किलो पार कर गया। किसानों को एक क्विंटल सरसों का दाम 8000 से 8100 रुपए तक मिला। दो साल पहले सरकार ने विदेशी तेल पर बढ़ाए टैक्स को कम कर दिया। इससे विदेश से पाम, राइसब्रान, पाम, कनोला, सोया और अन्य आयल की बंपर आवक होने लगी। विदेशी तेल बाजार में 75 से 80 रुपए किलो के भाव मिलते हैं। इससे सरसों तेल की मांग घटी और सरसों के दाम भी लुढ़कर 6000 से नीचे आ गया। वर्तमान में सरसों का भाव 5300 रुपए प्रति क्विंटल है। इस प्रकार दो साल में सरसों के भाव 2700 रुपए क्विंटल तक कम हो गए। उधर, खाद, बीज, सिंचाई महंगी हो गई।

- यह बात सही है कि सरसों का रकबा कई साल से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार लक्ष्य और पिछले साल से भी कम बोवनी हुई है। इसके पीछे का कारण सरसों का दाम कम होना ही है।
पीसी पटेल, संचालक, कृषि विभाग मुरैना

- सरकार ने विदेशी तेलों पर टैक्स बढ़ाया तो सरसों तेल की मांग बढ़ी, किसान व तेल व्यापारियों को फायदा भी हुआ, लेकिन जैसे ही विदेशी तेलों की बंपर आवक शुरू हुई, सरसों तेल का कारोबार ठप हो गया। मुरैना की अधिकतर मिलें बंद हैं।
मनोज जैन, तेल मिल संचालक, मुरैना

- खेती को बेहतर बनाने के लिए जुटे 14 इनोवेटर्स

फसलों की बीमारी और कीड़ों की पहचान करने वाला ऐप बना रहा आईआईटी

इंदौर। जागत गांव हमार

आईआईटी इंदौर में रूरल इनोवेटर्स कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया। इसमें इनोवेटर्स और उद्यमियों के एक बड़े समूह को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, उसके माध्यम से सहायता करने और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने नवाचारों को लेकर विचार साझा करने का एक मंच प्रदान किया गया। इस दौरान, प्रतिभागियों ने कॉन्क्लेव में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया और उनके लिए संभावित समाधान बताए। कॉन्क्लेव में ग्रामीण इनोवेटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों और आने वाले 10 वर्षों में अपेक्षित ग्रामीण इनोवेशन पर चर्चा शामिल रही। इसके अलावा, इस अवसर पर 14 से अधिक इनोवेटर्स ने भी अपने इनोवेशन का प्रदर्शन किया। यह कॉन्क्लेव ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी इंदौर द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया।

कई संगठनों और संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा आईआईटी- आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा, आईआईटी इंदौर ग्रामीण भारत के सामने आने वाली समस्या की पहचान करने के लिए आस-पास के संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहभागिता, सतत, पारदर्शी और लैंगिक-संवेदनशील प्रक्रियाओं को अपनाकर लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उचित और अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से यह काम किया जाएगा।

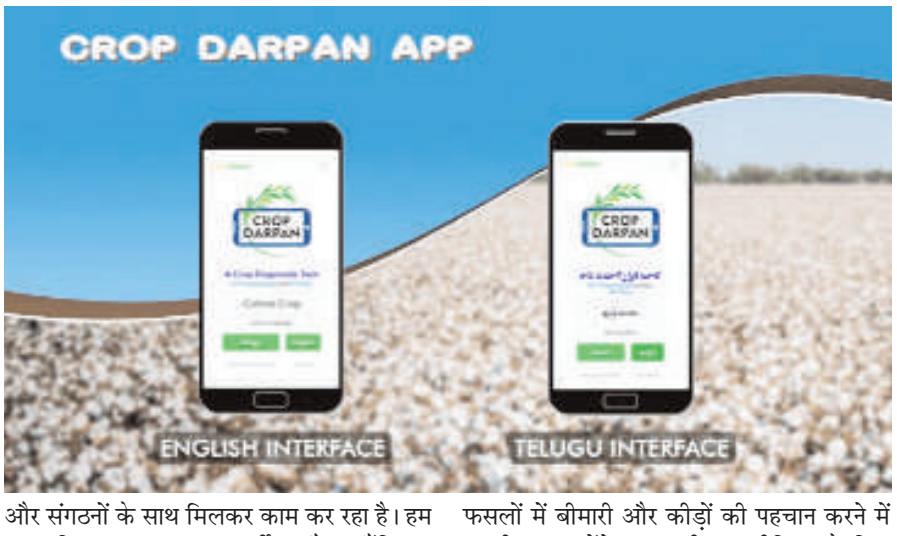

भूमिगत जल प्रबंधन में भी मिलेगी मदद- सुहास जोशी ने कहा कि हम कई ऐप विकसित करने के अंतिम चरण में हैं, जो किसानों को भू-जल प्रबंधन और सोयाबीन के पौधों और आलू की फसलों में बीमारी और कीड़ों की पहचान करने में काफी मदद करेंगे। जनजातीय आजीविका के लिए तकनीकी नवाचार कार्यक्रम तितली के तहत, हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को समझने और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान विकसित करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हम उनकी जरूरतों को समझने और व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए इंदौर और मध्य प्रदेश के आस-पास के उद्योगों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं।

ग्रामीण गतिविधियों के आसान इंटरफेस बनाने की तैयारी

ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी इंदौर का लक्ष्य कौशल विकास, लघु-स्तरीय उद्यमिता, मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास, लैंगिक विविधता के लिए पहुंच तथा अवसर और विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों से जुड़े ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च करने हेतु उपयोगकर्ता के लिए आसान इंटरफेस विकसित करना है, जिनके लिए ग्रामीण उद्यमियों को प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच के साथ अपने उत्पादों को विकसित करने और बेचने में मदद करने और कौशल तथा आउटरीच के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े समुदायों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर, उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सुहास जोशी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, सीआरडीटी आईआईटी दिल्ली, डॉ. देबप्रिया दत्ता, प्रमुख और वरिष्ठ सलाहकार -सीड डिवीजन, डीएसटी, डॉ. नेहा गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, राज्य नीति और योजना आयोग, मध्य प्रदेश , प्रोफेसर पारुल ऋषि, आईआईएफएम भोपाल, श्री सिद्धार्थ जैन, सीईओ, इंदौर जिला पंचायत, भारती ठाकुर, सचिव, नर्मदा, प्रोफेसर संदीप चौधरी, डीन (प्रशासन) और डॉ. देबायन सरकार, प्रमुख सीआरडीटी ने भाग लिया।

पीएचई मंत्री बोलीं-आवश्यक हो तो पुनः बनाए प्रस्ताव

-जल जीवन मिशन और जल निगम के कार्यों की समीक्षा

जल जीवन मिशन में हर गांव बसाहट और टोला हो शामिल

-हर घर जल पहुंचाने के सभी कार्य गति व गुणवत्ता के हो

भोपाल। जागत गांव हमार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी जिला अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन और मप्रजल निगम के जिले में संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय पुन्हार, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू और मोनिका बट्टी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री उइके ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव, हर बसाहट, हर मोहल्ला शामिल होना चाहिए। सभी को घर तक शुद्ध पेयजल मिले। विभाग के अधिकारी एक बार पुनः फील्ड में जांच कर और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर देख लें, कहीं कोई बसाहट या मोहल्ला छूट तो नहीं गया है। आवश्यकता पड़ने पर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर भेजें।

क्षेत्र में जाकर पुनः जांच लें- विशेषकर हर्रई और अमरवाड़ा क्षेत्र में जाकर पुनः जांच लें। इसमें सभी छात्रावासों और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टेप वाटर सुनिश्चित हो। पानी सभी को मिले, जल है तो जीवन है। जल जीवन मिशन और जल निगम के सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ और समय में पूर्ण कराएं।

1538 एकल ग्राम योजना स्वीकृत- कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में कुल 1538 एकल ग्राम योजना स्वीकृत हैं, 1456 में कार्यादेश जारी हो चुके हैं। मध्यप्रदेश जल निगम के अधिकारियों द्वारा जिले में संचालित समूह जल प्रदाय योजनाओं जिसमें पूर्ण हो चुकी मोहखेड़ ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना और चालू वर्ष में स्वीकृत माचागोरा ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना की जानकारी प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव शासन को भेजे

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन मिशन के अंतर्गत भारिया हितग्राहियों के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए के 5650 कार्यों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। बैठक में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जैसवाल, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, अपर कलेक्टर केसी बोपचे व वनमंड लाधिकारी, सहित सभी विभागों के प्रमुख एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही, सरकार सख्त

सीहोर में दो कंपनी के 33 गांवों की नल-जल का ठेका निरस्त

इधर, सीहोर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घोर लापरवाही बरतने और कार्य समय सीमा में नहीं करने पर मेसर्स डब्लू कन्स्ट्रक्शन कंपनी एवं मेसर्स अम्बकेश्वर स्टील प्राइवेट लिमिटेड का ठेका निरस्त कर दिया गया है। गत दिनों जल जीवन मिशन के निर्माण के कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाही और कार्यों में विलंब होना पाए जाने पर इन कंपनी के 33 गावों की नल जल योजना के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि मेसर्स डब्लू कन्स्ट्रक्शन कंपनी एवं मेसर्स अम्बकेश्वर स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिले के आष्टा विकासखंड एवं सीहोर में जल जीवन मिशन के कार्य किए जा रहे थे। कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इन दोनों कन्स्ट्रक्शन कंपनियों के कुल 33 ग्रामों की नलजल योजना के कार्यों के अनुबंध निरस्त किए गए हैं। इसमें मेसर्स डब्लू कन्स्ट्रक्शन कंपनी के अनुबंध क्रमांक 09/21-22 अंतर्गत ग्राम मोलूखडी, जताखेड़ा, हरनाबदा, बडघाटी, कन्नौदमिर्जी एवं मेसर्स अम्बकेश्वर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध क्रमांक 01/2021 2022 अंतर्गत ग्राम पाडलिया, सिराडी, कनपोन, सतपोन, मगरदीखुर्द एवं सरखेड़ा अनुबंध क्रमांक 40/2021-2022 अंतर्गत कुल 22 ग्रामों के कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार कुल 33 ग्रामों की नल-जल योजना के कार्यों के अनुबंध निरस्त किए गए हैं।

कलेक्टर-तहसीलदार से किसानों ने लगाई गुहार

साहब! हमारी जमीन ले लो मगर पेड़-पौधों को बचा लो

उज्जैन। जागत गांव हमार

चन्दुखेड़ी स्थित भूमि पर लगाए गए 200 से अधिक आम, जामफाल, कटहल, अमरूद, संतरा, चिकू, अनार, खिरनी सहित कई दुर्लभ एवं फलदार वृक्षों को बचाने की गुहार वहां के किसान परिवारों ने संभागायुक्त, कलेक्टर, वनमंडल अधिकारी, तहसीलदार के समक्ष लगाई है। किसानों ने कहा कि बड़नगर रोड पर बन रहे राष्ट्रीय राज मार्ग उज्जैन से बदनावर में सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार पीली मिट्टी निकाल रहे हैं। उक्त भूमि पर लगे वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है। इस कारण यहां पर्यावरण एवं जीव जन्तु, पशु, पक्षी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि में 5 हेक्टेयर भूमि लगभग 25 बीघा भूमि से मिट्टी खोदी जा चुकी है, केवल मात्र उक्त भूमि जिसमें वृक्ष लगे हैं शेष है। उक्त वृक्ष लगे वन में भी ठेकेदार ने खुदाई प्रारम्भ कर दी है। जिस कारण मिट्टी का क्षरण हो रहा है तथा पेड़ पौधे एवं जीव जन्तु को भारी नुकसान हो रहा है। हिन्दुलाल एवं कमल पिता नागुलाल निवासी नलवा ने बताया कि इन पेड़ पौधों को बच्चों की तरह पाला है। सरकार चाहे तो पूरी जमीन ले ले लेकिन इन पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने दे। 20 वर्षों से लगे पौधे पर्यावरण के लिए एवं पशु पक्षी के लिए लाभदायक होकर अत्यधिक जनउपयोगी वृक्ष है।

किसानों की कृषि योग्य भूमि

आस-पास अन्य किसानों की कृषि योग्य भूमि है, लेकिन ठेकेदार द्वारा खुदाई किए जाने के कारण अन्य कृषकों की कृषि योग्य भूमि में भी मिट्टी का भरण हो रहा है, जिससे अन्य किसानों की कृषि भूमि एवं फसल भी प्रभावित हो रही है। किसानों ने कहा कि उक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम खरेट एवं नलवा में अन्य भूमियां स्थित है जिनमें से मिट्टी की खुदाई की जा सकती है, उक्त भूमि के आस-पास कोई वन या अन्य किसान की भूमि भी नहीं है।

औषधीय वृक्ष लगे

नदी किनारे की इस भूमि खुदाई से पर्यावरण, जीव जन्तु एवं अन्य किसानों को किसी प्रकार का कोई हानि या क्षति नहीं होगी। किसानों ने मांग की कि जनहित में ग्राम चन्दुखेड़ी सर्वे नंबर 65 की लगभग 4 बीघा में स्थित वन जिसमें लगभग 200 से अधिक फलदार, दुर्लभ एवं औषधीय वृक्ष लगे है उसका संरक्षण करते हुए उक्त भूमि पर की जा रही खुदाई को रुकवाई जाए।

पेड़ों की हत्या कर रहे ठेकेदार

किसानों ने बताया कि जिस जगह पेड़ पौधों की हत्या पर ठेकेदार उतारू हैं। वह क्षेत्र उज्जैन दक्षिण विधानसभा में आता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा रोप रहे हैं, लेकिन वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री बने डॉ. मोहन यादव के क्षेत्र में सड़क ठेकेदार 200 पेड़ पौधों की हत्या करने पर उतारू हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इतने पेड़ पौधों की हत्या होने से रोकें।

गौशाला में बीमार गायों को नोंच रहे कुत्ते-कौव

तीन महीने में 300 गायों की मौत ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगा शवों के ढेर

मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसे रजिस्टर में लिखना भी बंद कर दिया

राजगढ़ जिले की गौशालाओं में आए दिन गाय और बछड़े तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। बीमार पड़ी गाय को कुत्ते और कौवे नोंचकर खा रहे हैं। गायों की दुर्दशा के ऐसे दृश्य ज्यादातर गौशालाओं में देखने को मिल जाएंगे। मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसे रजिस्टर में लिखना बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात की वजह कड़ाके की ठंड के साथ ही गौशाला का कुप्रबंधन भी माना जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। राजगढ़ जिले में लगातार हो रही गायों की मौत की जानकारी मिलने पर जागत गांव हमार की टीम ने गौशालाओं की पड़ताल की पढ़िए रिपोर्ट...।

राजगढ़। जागत गांव हमार

राजगढ़ जिले में 128 सरकारी गौशालाएं हैं। इतनी संख्या में यहां गौशालाएं होने के बाद भी आखिर गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। इसे समझने टीम सबसे पहले खिलचीपुर में स्थित सबसे बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में पहुंची। मप्र सरकार से अनुदान प्राप्त इस गौशाला की क्षमता 630 गायों की है। टीम ने पाया कि गौशाला के अंदर खुले मैदान में सैकड़ों गाय कीचड़ में खड़ी हुई थीं। गोबर नहीं उठाने की वजह से मिट्टी के साथ मिलकर यह पूरा एरिया दलदल सा बन गया है। गौशाला के अंदर बने कमरे और टीन शेड लगे हॉल में गाय और बछड़ों के जगह-जगह शव पड़े थे। इलाज नहीं मिलने से कई गाय बुरी तरह तड़प रही थीं। कुत्ते और कौवे, बीमार गाय को नोंच रहे थे। उनसे बचने के लिए गाय छटपटा रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। ऐसे दृश्य को देखकर टीम लगातार चार दिनों तक यहां पहुंची। पहले दिन मृत मिली गाय और बछड़ों के 6 शव का आंकड़ा चार दिनों में 32 तक पहुंच गया। यहां रखे रजिस्टर को देखने पर पता चला कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के तीन महीने में यहां 300 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। लगातार मौतें होने से पिछले दो-तीन महीने से रिकॉर्ड में मौतों को शामिल ही नहीं किया गया है।

गौशाला के चौकीदार रतनलाल कहते हैं कि यहां गाय की मौत होने पर रजिस्टर में एंट्री की जाती है। ठंड के बाद गायों की मौत की संख्या बढ़ गई है। मृत गायों को उठाकर ले जाने वाले नगर परिषद के कर्मचारियों ने रजिस्टर में अब संख्या लिखना बंद कर दिया है।

630 की क्षमता वाली गौशाला में 1100 गाय

श्री कृष्ण गौशाला समिति के सचिव राधेश्याम गुप्ता बताते हैं कि हमारी गौशाला की कैपेसिटी 630 गाय की है, लेकिन वर्तमान में यहां 1100 से अधिक गाय मौजूद हैं। इतनी गाय आईं कहां से, यह पूछने पर कहते हैं कि इस समय खेतों में फसल लहलहा रही है। ग्रामीण फसलों को बचाने के लिए गायों को गौशाला में छोड़कर जा रहे हैं। जगह नहीं होने का हवाला देते हैं तो वे विवाद करते हैं। हमें धमकाकर गायों को छोड़ जाते हैं।

जिन गायों को लोग लेकर आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर की हालत खराब होती है। वे इतनी कमजोर होती हैं कि इतनी गायों के बीच रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण तो यहां गाय लेकर आते ही हैं। खिलचीपुर नगर से भी बीमार और घायल गायों को नगर परिषद के कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं। इनके लिए हमने अलग हॉल बना रखा है। अब तक जो गाय यहां पर मरी हैं, उनमें बीमार या फिर कमजोर गाय जो पॉलीथिन खाती हैं, उनकी हुई है। हम गौशाला में गायों को रोज चारा डालते हैं। गायों के लिए सेंधा नमक तक मंगवा रखा है। यहां पर गाय की मौत भूख या प्यास से हुई है, यह कहना पूरी तरह से गलत है। पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम और बारिश की वजह से कुछ गाय निमोनिया से पीड़ित हुई हैं, उनकी जरूर मौत हुई है।

नगर परिषद के तीन कर्मचारियों की ड्यूटी शव उठाने में लगी

गुप्ता ने बताया कि मृत गायों को यहां से लेकर जाने का काम खिलचीपुर नगर परिषद के कर्मचारी करते हैं। तीन कर्मचारी गायों के शवों को उठाने के लिए लगे हुए हैं। ये नगर परिषद के वाहन से शवों को खिलचीपुर से करीब तीन किलोमीटर दूर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लेकर जाते हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड के बारे में पता चलने पर टीम वहां पर भी पहुंची। यहां का दृश्य भी विचलित करने वाला था। खुले मैदान में जगह-जगह मृत गाय पड़ी हुई थीं। शवों को चील-कौवे और कुत्ते नोच रहे थे। टीम ने शवों के पास जाने की कोशिश की तो खूंखार हो चुके कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के ढेर के बीच सैकड़ों भूखी गाय तड़पती नजर आईं। कुछ तो पॉलीथिन खा रही थीं। टीम ने गौशाला में गायों की हुई मौत को लेकर खिलचीपुर में पदस्थ पशु चिकित्सक डॉ. मधुसूदन शाक्यवार से बात की। उनका कहना है कि पॉलीथिन खाने के बाद गाय कमजोर हो जाती हैं और ठंड में शरीर का तापमान मेंटेंन नहीं कर पाती हैं। यहीं मौत की वजह बनती है।

शवों को खुले में फेंक रहे हैं तो यह गलत है: एसडीएम

खिलचीपुर एसडीएम अंकिता जैन ने कहा कि गौशाला का मैटर मेरे संज्ञान में आया था। पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मौके पर खुद गई थी। गौशाला में क्षमता से अधिक गाय हैं। वहां के अध्यक्ष से बात की और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। इस संदर्भ में आगे कार्रवाई की जाएगी। गांवों में जो गौशालाएं हैं, वहां संख्या से आधी गाय भी नहीं हैं। ऐसा है तो इस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा यदि खुले में गायों के शवों को फेंका जा रहा है तो यह पूरी तरह से गलत है। मैं खुद जाकर देखूंगी। ऐसा मिला तो सख्त कार्रवाई करूंगी।

सेमली कांकड़ : गौशाला के पिछले हिस्से में गायों के कंकाल पड़े मिले

यहां गौशाला के मेन गेट पर ताला लटक रहा था। चौकीदार अपने खेत पर काम कर रहा था। आगे ताला देख टीम गौशाला के पिछले हिस्से में पहुंची। यहां मैदान में जगह-जगह गाय की हड्डियां पड़ी हुई थीं। कुछ गायों के शव को कुत्ते नोंच रहे थे। टीम पीछे से गौशाला में घुसी तो 25 से 30 गाय नजर आईं। उनकी हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी। गांव में घूमे तो गौशाला के चौकीदार इंदर सिंह मिल गए, उन्होंने बताया कि गौशाला में 35 गाय हैं। यहां 143 गाय दर्ज हैं, जबकि सिर्फ 30 गाय ही मिलीं।

मुंडला : खाने के लिए न चारा-भूसा था, न कोई देख-रेख करने वाला

कुछ साल पहले बनाई गई इस गौशाला के हाल तो और ज्यादा खराब हैं। मेन गेट टूटा हुआ था और उस पर भी ताला लटका था। एक हॉल में करीब 30 गाय थीं, जबकि दूसरा खाली पड़ा था। न इनके खाने के लिए यहां चारा-भूसा नजर आया, न कोई इनकी देखभाल के लिए मौजूद था। गौशाला के एक कोने में बछड़े का शव पड़ा हुआ था।

हिनोतिया: लाइट तक नहीं, सभी गेट टूटे मिले

2023 में बनकर तैयार इस गौशाला का मेन गेट रस्सी से बंधा हुआ है। चौकीदार मांगीलाल ने रस्सी खोली। भीतर जाने पर पता चला कि यहां के सभी गेट टूटे हुए हैं। गायों को चारा-भूसा डालने के लिए बनाई गई ढेल भी टूट चुकी है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। भीतर अंधेरे में कुछ गाय जमीन पर तड़पती मिलीं। मांगीलाल कहते हैं कि लाइट नहीं होने से यहां अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। रिकॉर्ड में 138 गाय दर्ज हैं, जबकि 60 गाय थीं।

बोवनी-सिंचाई और उन्नत किस्मे किसानों के लिए लाभदायक

फरवरी-मार्च में खीरे की पैदावार शुरू कर कमाएं अच्छा मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

कद्दूवर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इसका बाजारों में बहुत ज्यादा मांग होती है। इसलिए कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान खीरे की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान इसकी खेती से कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं खीरा बहुत जल्दी तैयार होने वाली फसल है। इसकी बोवनी के दो महीने बाद ही इसमें फल लगना चालू हो जाता है। खीरा भोजन के साथ सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है। ये गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। गर्मी के समय बाजारों में इसकी डिमांड बने रहने से किसानों को भाव अच्छा भी मिलता है। अगर किसान खीरे की खेती वैज्ञानिक विधि से करें तो इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्र में बरसात के मौसम में भी इसका ज्यादा उत्पादन होता है। इस फसल की खेती महाराष्ट्र में लगभग 3711 हेक्टेयर में की जाती है।

कैसी होनी चाहिए मिट्टी- खीरे को रेतीली दोमट और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी में अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6-7 के बीच होना चाहिए।

उन्नत किस्में

पूसा संयोग, पूसा बरखा, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, स्वर्ण अगेती, पंजाब सलेक्शन, खीरा 90, कल्यानपुर हरा खीरा, खीरा 75, पीसीयूएच- 1, पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण शीतल आदि इसकी अच्छी किस्म मानी जाती हैं। पूसा संयोग एक हाइब्रिड किस्म है जो 50 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 200 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। जबकि पूसा बरखा खरीफ के मौसम के लिए है। इसकी औसत पैदावार 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उधर, स्वर्ण शीतल चूर्णी फफूंदी और श्याम वर्ण रोग प्रतिरोधी किस्म है।

बोवनी का समय

ग्रीष्म ऋतु के लिए इसकी बोवनी फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है। वर्षा ऋतु के लिए इसकी बुवाई जून-जुलाई में करते हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बोवनी मार्च और अप्रैल माह में की जाती है।

बीज की मात्रा

एक एकड़ खेत के लिए 1.0 किलोग्राम बीज की मात्रा काफी है। ध्यान रहे बिजाई से पहले, फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए और जीवनकाल बढ़ाने के लिए, अनुकूल रासायनिक के साथ उपचार जरूर करें। बिजाई से पहले बीजों का 2 ग्राम कप्तान के साथ उपचारित किया जाना चाहिए।

किसान कब करें तुड़ाई

खीरे के फलों को कच्ची अवस्था में तोड़ लेना चाहिए जिससे बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल सके। फलों को एक दिन छोडक़र तोडऩा अच्छा रहता है। फलों को तेजधार वाले चाकू या थोड़ा घुमाकर तोडना चाहिए ताकि बेल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। खीरे को तोड़ते समय ये नरम होने चाहिए, पीले फल नहीं होने देना चाहिए।

रंगीन वैरायटी की शुरू हो सकती है खेती

देश में सफेद नहीं, अब नीले कपास का आएगा जमाना

भोपाल। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों को कपास की फसल के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की एक बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कपास की खेती पर ही निर्भर है। महाराष्ट्र देश का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, लेकिन यह जानकर सभी को आश्चर्य होगा कि आज हम जिस सफेद कपास को देखते हैं वह 100 साल पहले ऐसा नहीं था। कई रंगों वाली किस्में होती थीं और इसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती थी। लगभग 1950 तक आंध्र प्रदेश से जापान तक खाकी कपास के निर्यात के रिकॉर्ड हैं। अब नीले कपास पर बात हो रही है। वर्तमान में, शोधकर्ता नीली कपास की किस्म विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी किस्म जो जींस के उत्पादन में बहुत क्रांतिकारी हो सकती है, जो बहुत लोकप्रिय हो सकती है। इसके लिए वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नील की फसल के जीन को कपास में लाकर ऐसा बदलाव करना संभव है।

संस्थान के पास रंगीन कपास की 40 किस्में- बेशक, जैसे-जैसे यह उद्योग मशीनीकृत होता गया, कपास की नई किस्में सामने आईं। पूरी दुनिया में शुद्ध सफेद, लंबे रेशे वाले कपास का बोलबाला हो गया। अब किसानों के खेतों में बीटी के अलावा किसी अन्य प्रकार की कपास देखने को नहीं मिलती। भारत के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के पास कपास की 6000 किस्मों का संग्रह है। इनमें रंगीन कपास की लगभग 40 किस्में हैं।

इसलिए पड़ रही जरूरत

कपड़ा उद्योग में विभिन्न रासायनिक रंगों के प्रयोग से मानव जीवन पर कई प्रकार से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस रंग की उत्पादन प्रि या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पानी में कई विषैली धातुएं मिल जाती हैं। इससे इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा होता है। इसके समाधान के रूप में, इन रासायनिक रंगों का उपयोग कम करने की जरूरत है।

किस्में बनाने में मिली सफलता

गौरतलब है कि 1980 के दशक के आसपास, कपास प्रजनकों ने अपना ध्यान रंगीन कपास की ओर लगाया था। अमेरिकी कपास ब्रीडर सैली फॉक्स ने आठ साल के अथक प्रयासों के बाद एक लंबी रेशे वाली कपास की किस्म विकसित की। वो ग्रे, पीला, नारंगी और गुलाबी जैसे रंगों वाली किस्में बनाने में सफल रहीं।

भारत में उत्पादन कम

अब एक बार नीले कॉटन की किस्म विकसित करने की तैयारी है। वर्तमान में, रंगीन कपास मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पेरू और इजराइल में उगाया जाता है। भारत में इसका अनुपात अभी भी अधिक नहीं है। नागपुर स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने वैदेही 95 नामक भूरे सूत की कपास किस्म विकसित की है।

सोयाबीन की किस्मों के बीजों भंडारण के साथ गुणवत्ता को भी बरकरार रखने में मिलेगी मदद

जबलपुर कृषि विवि में डिह्यूमिडीफाइड बीज भंडारण का लोकार्पण

जबलपुर। जागत गांव हमार

जबलपुर। जबलपुर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली एवं बीज विज्ञान संस्थान मऊ (उप्र) के सहयोग से 5 हजार क्विंटल क्षमता वाले एसी डिह्यूमिडीफाइड बीज भंडारण एवं थ्रेसिंग लोर के निर्माण के लिए राशि प्रदान की गई थी, जो विवि के पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग के अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन इकाई में निर्माण किया गया। नवनिर्मित अधोसंरचना का लोकार्पण डॉ. संजय कुमार, निदेशक, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ के मुख्य आतिथ्य एवं कुलपति डॉ. पीके मिश्रा, जनेकृविवि की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉ. संजय कुमार ने बताया की डिह्यूमिडीफाइड बीज भंडारण के लोकार्पण से विवि में उत्पादित सोयाबीन की विभिन्न किस्मों के बीजों के भंडारण के साथ-साथ उनके गुणवत्ता को भी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि भविष्य में अन्य फसलों के लिए इस तरह के भंडारण विधि को अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जीके कौतू ए संचालक प्रक्षेत्र डॉ. आरएस शुक्ला ने भी संबोधित किया। वहीं किसान गोष्ठी के माध्यम से विवि के वैज्ञानिकों ने रबी फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)